

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज हुकमसिंह वगैरा बनाम चनणसिंह वगैरा धारा 88,53,188, प्रकरण संख्या 70/2023	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
----------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------

10.07.2024

पत्रावली आज पेश हुई। वक्कुलाय उपस्थित। पत्रावली में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सीपीसी सपठित धारा 151 सीपीसी पर बहस सुनी गई।

अधिवक्ता प्रतिवादी द्वारा आदेश 07 नियम 11 के प्रार्थना पत्र में वर्णित किया गया है कि प्रतिवादी ने प्रार्थना पत्र पर बहस करते हुए निवेदन किया कि वादी ने विवादग्रस्त भूमि बाबत घोषणा बंटवाडा स्थाई निषेधाज्ञा का वाद पेश किया गया तथा उपरोक्त भूमि बाबत अनुतोष चाहा है तथा वादपत्र में भूमि में वर्णित खसरान् को भभूतसिंह का होने का कथन किया एव उक्त भूमि बाबत पूर्व में वाद के विचारण होने के अभिकथन किए है तथा घोषणात्मक एव बंटवाडा की डिग्री चाही है जबकि उक्त भूमि बाबत पूर्व में ही इसी अनुतोष को लेकर वाद चला जो राजीनामा से डिग्री हो गया तथा वाद में पारित डिग्री के आधार पर राजस्व रेकॉर्ड में तब्दीली लगभग 50 वर्ष पूर्व ही कर दी गई है ऐसी स्थिति में धारा 7 नियम 11 सीपीसी के तहत उपरोक्त वाद विधि द्वारा वर्जित होने से वादपत्र नामजूर किया जाने का निवेदन किया गया।

अधिवक्ता वादी द्वारा बहस कर निवेदन किया कि सहायक जिलाधीश जोधपुर में वाद संख्या 40/1967 के निर्णय के आधार पर नामान्तरकरण संख्या 177 एव 178 दर्ज नहीं किए गये तथा वाद के निर्णय की तारीख अंकित नहीं है ऐसी स्थिति में प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सीपीसी खारिज किया जाने का निवेदन किया गया।

बहस पर मनन किया गया पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेज का अवलोकन किया गया वादी ने अपने वाद पत्र में घोषणा का अनुतोष चाहा है तथा बंटवाडा का अनुतोष चाहा है तथा वाद पत्र में भूमि पूर्व में भभूतसिंह की होने तथा म्यूटेशन संख्या 177 एव 178 द्वारा प्रतिवादीगण के नाम से पूर्व होने का कथन किया गया साथ ही वाद पत्र में सहायक जिलाधीश जोधपुर में वाद कार्यवाही होने कथन किया है वाद पत्र के साथ प्रस्तुत जमाबंदी एव म्यूटेशन से वर्तमान में विवादग्रस्त भूमि के कुछ खसरे प्रतिवादीगण के नाम से दर्ज है तथा प्रतिवादीगण द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में उक्त अंकन राजस्व न्यायालय के फैसले के परिणाम स्वरूप आये होने का कथन किया ऐसी स्थिति में न्यायालय के समक्ष आता है कि वर्तमान में राजस्व रेकॉर्ड में अंकन न्यायालय के निर्णय की पालना में हुए नामान्तरकरण से आये है इसमें प्राथमिक तौर पर पूर्व में पक्ष कारान् के बीच विवाद होने एव वाद के निर्णय के आधार पर अंकन आया है तथा उस निर्णय के न होने बाबत वादी ने कोई आपत्ति नहीं की और फैसले का प्रति भी प्रतिवादीगण द्वारा वादी को उपलब्ध करवा दी थी ऐसी स्थिति में धारा 7 नियम 11 सीपीसी के अनुसार कोई भी न्यायालय पूर्व में वाद के निर्णय हो जाने के बाद नये वाद का विचारण न करने के प्रावधान है। प्रार्थना पत्र 7 नियम 11 सीपीसी धारा 11 के तहत ज्यूडिकाटा का सिद्धांत के अनुसार कोई भी न्यायालय किसी ऐसे वाद या विवाधक का विचारण नहीं करेगा जिसमें प्रत्यक्षत और विवाध विषय उसी हक के अधीन मुकदमा करने वाले उन्ही पक्षकारों के बीच या ऐसे पक्षकारों के बीच के जिनसे व्युत्पन्न अधिकार के अधीन वे या उनमें से कोई दावा करते है, किसी पूर्ववर्ती वाद में भी ऐसे न्यायालय में प्रत्यक्षत-और सारत विवाध रहा है जो पश्चावर्ती वाद का जिसमें ऐसा विवाधक वाद में उठाया गया है विचरण करने के लिये सक्षम था और ऐसे न्यायालय द्वारा सुना जा चुका है और अंतिम रूप से विनिक्षित किया जा चुका है ऐसी स्थिति में वादी द्वारा प्रस्तुत वाद विधि द्वारा वर्जित होना प्रतीत होने से प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सीपीसी स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है तथा प्रार्थना पत्र स्वीकार कर वादीगण का वाद पत्र नामजूर का वाद खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।



सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,  
लुणी